खाद्य मुद्रास्फीति से कैसे निपटें और कैसे नहीं?

लेखक- अशोक गुलाटी (इंफोसिस चेयर प्रोफ़ेसर) एवं रितिका जुनेजा
(ICRIER में सलाहकार)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

09 मई, 2022

गेहूँ के उत्पादन को लेकर डर के कारण सरकार को निर्यात प्रतिबंध की ओर रुख नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से अनाज पर, जिसकी कीमतें अब तक के उच्चतम स्तर पर हैं।

महँगाई पर काबू पाने के लिए गवर्नर शक्तिकांत दास के नेतृत्व वाली आरबीआई टीम को रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट्स (bps) और कैश रिजर्व रेशियो (CRR) को 50 बीपीएस बढ़ाने के लिए बधाई दी जानी चाहिए। उच्च मुद्रास्फीति हमेशा गरीबों और बैंकों में अपनी बचत रखने वालों पर एक निहित कर है। उनकी बचत का वास्तविक मूल्य मुद्रास्फीति के हर दौर के साथ कम हो जाता है क्योंकि जमा पर ब्याज अक्सर मुद्रास्फीति दर से काफी नीचे होता है। इसलिए, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना आरबीआई का एक महत्त्वपूर्ण जनादेश है।

सवाल यह उठता है कि क्या रेपो रेट और सीआरआर में बढ़ोतरी से महँगाई, खासकर खाद्य महँगाई पर नियंत्रण होगा? संक्षिप्त उत्तर है, "अभी नहीं"। स्थिति का हमारा आकलन यह है कि आरबीआई कम से कम 4 से 5 महीने तक पीछे रहा है और मौद्रिक नीति समिति की पिछली बैठकों में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में थोड़ी कमी देखी गई है। अगर आरबीआई को खोए हुए समय की भरपाई करनी है, तो उसे सिस्टम में अतिरिक्त तरलता को खत्म करने के लिए इस वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष 23) में रेपो दरों और सीआरआर को कम से कम तीन बार बढ़ाना होगा। फिर भी, खाद्य मुद्रास्फीति पर लगाम लगाना मुश्किल हो सकता है, जो समग्र उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) की तुलना में तेजी से बढ़ रही है।

इसका कारण सरल है। एफएओ (FAO's) के खाद्य मूल्य सूचकांक के अनुसार वैश्विक स्तर पर खाद्य कीमतें नए शिखर पर पहुँच रही हैं। महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधान और अब रूस-यूक्रेन युद्ध खाद्य कीमतों में इस वृद्धि में योगदान दे रहे हैं। भारत इस घटना से अछूता नहीं रह सकता है। जहाँ एक ओर इसने भारतीय कृषि निर्यात के लिए अवसर खोले हैं, वहीं दूसरी ओर, इसने खाद्य तेलों और उर्वरकों के आयात की कीमतों में वृद्धि के रूप में चुनौतियों का सामना किया है।

आइए हम यहाँ अनाज पर ध्यान देते हैं, जिनका भारत के खाद्य सीपीआई में सबसे अधिक भार है। भारतीय कृषि के इतिहास में पहली बार, अनाज निर्यात पहले ही 31 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) के रिकॉर्ड उच्च स्तर 13 बिलियन डॉलर (FY22) को पार कर चुका है। गेहूँ के निर्यात में 273 प्रतिशत से अधिक की अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है, जो वित्त वर्ष 2011 में 0.56 बिलियन डॉलर (या 2 एमएमटी) से लगभग चार गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2012 में 2.1 बिलियन डॉलर (या 7.8 एमएमटी) हो गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कृषि निर्यात को लेकर उत्साहित हैं, जो वित्त वर्ष 22 में पहली बार कुल मिलाकर $50 बिलियन को पार कर गया है। गेहूँ पर, जहाँ एक तरफ सरकार ने वित्त वर्ष 2013 में निर्यात

के लिए 10 एमएमटी का लक्ष्य रखा है, वहीं दूसरी तरफ गोयल ने हाल ही में एक साक्षात्कार में कहा कि यह 15 एमएमटी तक भी जा सकता है। इसने कई लोगों के बीच यह आशंका पैदा कर दी है कि क्या भारत हीटवेव के कारण मौजूदा फसल के उत्पादन अनुमान को 111 एमएमटी से घटाकर 105 एमएमटी करने और खरीद में भारी गिरावट के कारण 10 से 15 एमएमटी निर्यात कर सकता है। हालाँकि, चावल के निर्यात के बारे में बहुत कम बात होती है, जो वित्त वर्ष 2012 में 50 एमएमटी के वैश्विक बाजार में 20 एमएमटी को पार कर गया है। यह गेहूँ की तुलना में बहुत बड़ा आश्चर्य है।

गेहूँ के मामले पर कुछ चिंताएँ वाजिब हैं और हमें यह महसूस करने की जरूरत है कि जलवायु परिवर्तन पहले से ही हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। आईपीसीसी की पहले की रिपोर्ट के अनुसार, तापमान में हर एक डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के साथ, गेहूँ की पैदावार में लगभग 5 एमएमटी की कमी आने की संभावना है। यह गेहूँ की गर्मी प्रतिरोधी किस्मों को खोजने के लिए कृषि-आर एंड डी में बड़े पैमाने पर निवेश की माँग करता है और "जलवायु-स्मार्ट" कृषि के लिए मॉडल भी बनाता है। हम इस मामले में काफी पीछे हैं। लेकिन हम 800 मिलियन भारतीयों को मुफ्त भोजन वितरित करने में वक्र से बहुत आगे हैं, एक खाद्य सब्सिडी बिल के साथ जो कि वित्त वर्ष 2013 में केंद्र के शुद्ध कर राजस्व में से लगभग 20 लाख करोड़ रुपये में से 2.8 लाख करोड़ रुपये को पार करने की संभावना है।

क्या गोयल, जो कृषि-निर्यात को लेकर उत्साहित हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और पीएमजीकेएवाई को भी खाद्य मंत्री के रूप में तर्कसंगत बना सकते हैं, केवल गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को मुफ्त या सब्सिडी वाले भोजन के लिए लक्षित कर सकते हैं और उचित मूल्य वसूल कर सकते हैं। लब्बोलुआब यह है कि उसे बड़े पैमाने पर खाद्य सब्सिडी को प्रभावी ढंग से लक्षित करना है और खाद्य तेलों एवं उर्वरकों पर उच्च आयात बिल के लिए संसाधनों को बचाना है। खाद्य तेलों में मुद्रास्फीति लंबे समय से दहाई अंक में चल रही है और उस मोर्चे पर उपभोक्ताओं के लिए कोई राहत नहीं है।

हम (लेखक) लाभार्थियों को अनाज के बदले उनके जन धन खातों (एमएसपी के बराबर, प्लस 20 प्रतिशत) में नकद देने का विकल्प देने का सुझाव देंगे। एनएफएसए के तहत इसकी अनुमति है और ऐसा करने से वह बढ़ते खाद्य सब्सिडी बिल पर बचत कर सकता है।

गोयल को गेहूँ को लेकर किसी भी तरह के डर को दूर करने की भी जरूरत है जो उन्हें निर्यात प्रतिबंध की ओर जाने के लिए मजबूर कर सकता है। यह किसान विरोधी कदम होगा। हमारे पहले के नीति निर्धारण के साथ समस्या यह रही है कि यह गरीबों के नाम पर उपभोक्ताओं की रक्षा करने के प्रति पक्षपाती है, किसानों के लिए कीमतों को दबाने वाले बाजारों के माध्यम से-व्यापारियों पर स्टॉक सीमा लगाकर, न्यूनतम निर्यात मूल्य या निर्यात पर एकमुश्त प्रतिबंध लगाकर। हमें इस रास्ते से बचना चाहिए और कृषि-निर्यात को फलने-फूलने देना चाहिए।

भारतीय किसानों को अपनी आय बढ़ाने के लिए वैश्विक बाज़ारों तक पहुँच की आवश्यकता है और सरकार को भारतीय किसानों को विपणन लागत को कम करके और निर्यात के लिए कुशल रसद में निवेश करके अधिक कुशल निर्यात मूल्य श्रृंखला विकसित करने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए।

जीएस वर्ल्ड टीम इनपुट

IN THE NEWS

विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक: FAO

चर्चा में क्यों?

- संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (FAO) का खाद्य मूल्य सूचकांक मार्च में औसतन 159.3 अंक रहा और इसने फरवरी 2011 में 11 साल पहले के 137.6 अंकों के पहले के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।
- खाद्य और कृषि संगठन (FAO) ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि फरवरी की तुलना में मार्च में विश्व खाद्य कीमतों में लगभग 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- एफएओ अनाज (सेरेल) मूल्य सूचकांक फरवरी की तुलना में मार्च में 17.1 प्रतिशत अधिक था, जो यूक्रेन में युद्ध के परिणामस्वरूप गेहूँ और सभी मोटे अनाज की कीमतों में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी की वजह से हुआ।
- खाद्य मूल्य सूचकांक पर अपने विस्तृत नोट में एफएओ ने कहा, काला सागर क्षेत्र में शिपमेंट की आवाजाही में आई कमी की वजह से निर्यात का नुकसान हुआ और इस वजह से जहाँ वैश्विक कीमतें बढ़ी, वहीं आयात में कमी आई और माँग में वृद्धि हुई।

खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के बारे में

- यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भुखमरी-उन्मूलन हेतु किए जाने वाले प्रयासों का नेतृत्व करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है।
- वर्ष 1945 में खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत की गई थी और यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है।
- इसका उद्देश्य खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) का लक्ष्य सभी के लिए खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना तथा लोगों तक सक्रिय, स्वस्थ जीवन जीने हेतु पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाले भोजन की नियमित पहुँच सुनिश्चित कराना है।
- प्रत्येक वर्ष FAO की स्थापना की वर्षगाँठ की याद में विश्व में 16 अक्तूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है।

FAO की रणनीतिक रूपरेखा 2022-2031

- वर्ष 2021 के सम्मेलन में FAO के सदस्य देशों द्वारा 'रणनीतिक रूपरेखा' (Strategic Framework) 2022-2031 अपनाई गई थी।
- इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ते हुए, बेहतर उत्पादन, बेहतर पोषण, बेहतर पर्यावरण और बेहतर जीवन के लिए, कृषि-खाद्य प्रणालियों को अधिक कुशल, समावेशी, लचीला, और संवहनीय प्रकार में परिवर्तन करने के माध्यम से सतत विकास एजेंडा 2030 में सहयोग करना है।
- ये चार बेहतर (Four Betters) उद्देश्य- सतत विकास लक्ष्यों (SDGs), विशेषकर SDG 1 (निर्धनता-उन्मूलन), SDG 2 (भुखमरी-उन्मूलन), और SDG 10 (असमानता में कमी) को हासिल करने में सहयोग करने हेतु, FAO द्वारा लागू किए जाने वाले कार्य संयोजन-सिद्धांतो को अभिव्यक्त करते हैं।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक (World Food Price Index) मार्च में औसतन 159.3 अंक है।
2. खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत की गई थी।
3. FAO के खाद्य मूल्य सूचकांक को वर्ष 1996 में वैश्विक कृषि वस्तु बाज़ार के विकास की निगरानी में मदद के लिए सार्वजनिक रूप से पेश किया गया था।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(क) 1 और 3
(ख) 2 और 3
(ग) 1 और 2
(घ) उपर्युक्त सभी

Expected Question (Prelims Exams)

Q. Consider the following statements-

1. The World Food Price Index averaged 159.3 points in March.
2. The Food and Agriculture Organization was established in the year 1945 under the United Nations Organization.
3. The FAO's Food Price Index was introduced publicly in 1996 to help monitor the development of the global agricultural commodities market.

Which of the above statements are correct?

(a) 1 and 3
(b) 2 and 3
(c) 1 and 2
(d) All of the above

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. खाद्य मुद्रास्फीति से आप क्या समझते हैं? भारत में खाद्य मुद्रास्फीति के लिए जिम्मेदार कारकों का उल्लेख करते हुए खाद्य मुद्रास्फीति के समाधान हेतु उपाय सुझाए। (250 शब्द)

Q. What do you understand by food inflation? While mentioning the factors responsible for food inflation in India suggest measures to rectify food inflation. (250 Words)

Committed To Excellence

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।